

GS WORLD

एक ऐतरा संस्थान जो आपली वृद्धिवस्तु के लिए जाला जाता है...



16 - 31 Jan., 2019

**P
I
B**
PICTURE

B



DELHI CENTRE

629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Dwarka-96
Ph.: 7042772082/93, 98881365322

ALLAHABAD CENTRE

GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0522-2296079, 8728627579

LUCKNOW CENTRE

A-7, Sector-3, Puraniya Chauraha
Alliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8755456694

16-31 जनवरी, 2019

भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौता

PIB, (16 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
संबंधित मंत्री – संतोष गंगवार (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खान, परीक्षण और अनुसंधान केंद्र में सुरक्षा (एसआईएमटीएआरएस) के जरिए महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन खान एवं ऊर्जा विभाग, क्वीन्सलैंड प्रशासन, ऑस्ट्रेलिया के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।



प्रभाव

- सहमति पत्र से डीजीएमएस और एसआईएमटीएआरएस के बीच साझेदारी कायम करने में मद्द मिलेगी।
- जोखिम आधारित प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सम्मेलन, संगोष्ठी और अन्य तकनीकी बैठकों का आयोजन, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अकादमी और राष्ट्रीय खान आपदा केंद्र की स्थापना।
- डीजीएमएस में आर एंड डी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
 भारत सरकार (Government of India)

कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति

- यह सहमति पत्र हस्ताक्षर वाली तिथि से ही क्रियाशील हो जाएगा और तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

पृष्ठभूमि

- ऑस्ट्रेलिया में खान दुर्घटनाओं की दर विश्व में सबसे कम है।

- ऑस्ट्रेलिया जोखिमों की पहचान और खतरे के आकलन की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खान क्षेत्र के लिए जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं की संकल्पना और कार्यान्वयन के क्षेत्र में अग्रणी है।
- एसआईएमटीएआरएस खान सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में विशिष्ट प्रकार की विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

PIB, (16 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
संबंधित मंत्री – पीयूष गोयल (अतिरिक्त प्रभार)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल(कैबिनेट) ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एकिजम बैंक) के पुनर्पूजीकरण को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय निर्यात-आयात बैंक में नई पूँजी लगाने के लिए भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपये के पुनर्पूजीकरण बांड जारी करेगी।
- वित्त वर्ष 2018-19 में 4,500 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपये की दो किस्तों के जरिए इक्विटी लगाई जाएगी।



Exim
Export-Import Bank of India

- कैबिनेट ने एकिजम बैंक की अधिकृत पूँजी को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है। पुनर्पूजीकरण बांड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए जाएंगे।

प्रमुख प्रभाव

- एकिजम बैंक भारत के लिए प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी है।
- एकिजम बैंक में पूँजी लगाने से यह पूँजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाने और इसके साथ ही ज्यादा क्षमता के साथ भारतीय निर्यात के लिए आवश्यक सहायता देने में समर्थ हो जाएगा।
- नई पूँजी लगाने से भारतीय कपड़ा उद्योगों को आवश्यक सहायता देने, रियायती वित्त योजना (सीएफएस) में संभावित बदलावों, भारत की सक्रिय विदेश नीति और रणनीतिक मंशा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में नई ऋण रेखा (एलओसी) की संभावनाओं जैसी नई पहलों को बढ़ावा मिलेगा।

पृष्ठभूमि

- एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) की स्थापना एक संसदीय अधिनियम के तहत वर्ष 1982 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण, इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी।
- यह बैंक मुख्यतः भारत से निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराता है।
- भारत से विकासात्मक एवं बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक सहायता देना भी इसमें शामिल है।
- इसका नियमन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किया जाता है।

पहली राष्ट्रीय ईएमआरएस राष्ट्रीय स्पोर्ट मीट, 2019

PIB, (16 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – जनजातीय कार्य मंत्रालय
संबंधित मंत्री – जुएल ओराम

संदर्भ

- हाल ही में एकलब्ध मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के छात्रों के लिए प्रथम राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट मीट का उद्घाटन, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभार, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री, जी.एम.सी. बालयोगी स्टेडियम, हैदराबाद द्वारा किया गया।
- मंत्री ने इस अवसर पर समर्पित एक ऐप 'ईएमआरएस स्पोर्ट्स मीट' भी लॉन्च किया।
- इस आयोजन में 1775 छात्रों की भागीदारी रही।
- इसमें देश के 20 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 975 लड़के और 802 लड़कियां शामिल हैं।



- सरकार ने वर्ष 2022 तक 50% या अधिक आदिवासी आबादी और 20,000 या अधिक आदिवासी व्यक्तियों के साथ प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है।

- पहले से ही स्वीकृत 288 ईएमआरएस के अलावा लगभग 462 स्कूल स्थापित किए जाएंगे।

विशेषता

- इस स्पोर्ट्स मीट की प्रमुख विशेषता उत्तर में उत्तर-पूर्वी भारत से हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में केरल और पश्चिम में गुजरात के दूर-दराज क्षेत्रों के ईएमआरएस में पढ़ने वाले जनजातीय छात्रों को एक मंच उपलब्ध कराना है।

मतदाता जागरूकता मंच

PIB, (16 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – निर्वाचन आयोग
संबंधित मंत्री – ओम प्रकाश रावत

संदर्भ

- हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में मतदाता जागरूकता मंच (वोटर अवेयरनेस फोरम) का शुभारंभ किया।
- यह मंच विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाता पंजीकरण, मतदान कैसे करें, कहां पर चुनावी चर्चा करें आदि की जागरूकता पैदा करने का अनौपचारिक मंच है।
- यह मंच मतदाता पहचान पत्र बनाना, मतदान करना व मतदान में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम व बीवीपैट के विषय में संपूर्ण जानकारी देगा।

चुनाव पाठशाला



कोई मतदाता न छूटे

- चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिये सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य गैरसरकारी संगठनों को मद्दगार बनाने की पहल की है।
- राज्यों में भी यह प्रक्रिया शुरू करते हुये सत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता मंच का गठन होगा।

- इनमें राज्य और जिलों में सरकारी और गैर सरकारी विभागों के नोडल अधिकारियों, सीएसओ, कॉर्पोरेट और मीडिया को इस कवायद से अवगत कराया जायेगा।
- फोरम में संगठन के सभी अधिकारियों से इसके सदस्य बनने और संस्था के प्रमुख को फोरम का अध्यक्ष बनाये जाने का प्रावधान किया गया है।



उद्देश्य

- भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक कर मतदाता शिक्षा को सुविधाजनक बनाना है।
- मतदाता जागरूकता मंच सरकारी विभागों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ कॉर्पोरेट्स में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।
- निर्वाचन आयोग के 'स्वीप' कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थानों में मतदाता साक्षरता क्लब और बूथ स्तर पर चुनाव पाठशालाएं बनाई गई हैं।

मुख्य बिंदु

- मतदाता जागरूकता मंच को आयोग के निर्वाचक साक्षरता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है।
- यह पहल गत वर्ष 25 जनवरी को 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शुरू किये गये निर्वाचक साक्षरता क्लब (ईएलसी) कार्यक्रम का हिस्सा है।
- ईएलसी में शिक्षण संस्थानों तथा प्रत्येक मतदाता केन्द्र पर चुनाव पाठशाला में निर्वाचक साक्षरता क्लब बनाना है।
- जिससे औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर के लोगों को निर्वाचन जागरूकता के दायरे में लाया जा सके।

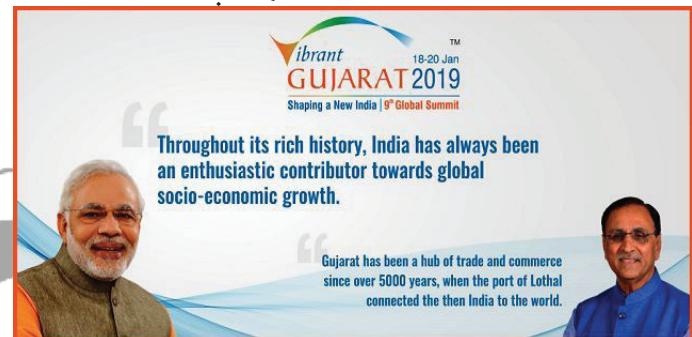
वाइब्रेंट गुजरात समिट

PIB, (17 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन के 9वें संस्करण का गांधीनगर में उद्घाटन किया।
- यह शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित किया गया। इसकी थीम 'शेपिंग ऑफ ए न्यू इंडिया' था।
- वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन 18 से 20 जनवरी, 2019 तक किया गया।

- वाइब्रेंट गुजरात समिट के हिस्से के रूप में कई प्रमुख कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा इस शिखर सम्मेलन का नौवां संस्करण अनेक पूर्णरूपण नए मंचों (फोरम) के शुभारंभ का भी साक्षी बना।
- इसका उद्देश्य इस शिखर सम्मेलन के दौरान ज्ञान साझा करने के स्वरूप में विविधता लाना और प्रतिभागियों के बीच नेटवर्किंग के स्तर को बढ़ाना है।



क्या है?

- वाइब्रेंट गुजरात समिट की परिकल्पना वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी जो उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे।
- इस शिखर सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गुजरात को फिर से एक प्रसंदीदा निवेश गंतव्य या राज्य के रूप में स्थापित करना था।
- यह शिखर सम्मेलन वैश्विक सामाजिक-आर्थिक विकास, ज्ञान साझा करने और प्रभावकारी साझेदारियां करने से जुड़े एंजेंडे पर विचार मंथन करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा।

मुख्य बिंदु

- इस सम्मेलन में करीब 15 लाख लोग और 100 से ज्यादा देशों के 3000 प्रतिनिधि पहुँचे।



- वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन राज्य की राजधानी के एक मैदान के लगभग दो लाख वर्गमीटर क्षेत्र हुआ।
- इस कार्यक्रम में लगभग 25 औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।
- इस शिखर सम्मेलन के द्वारा गुजरात में व्यापारिक अवसरों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

इसके सहभागी देश

- वाइब्रेंट गुजरात के पार्टनर देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, मोरक्को, नॉर्वे, पौलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, नीदरलैंड, यूएई, उज्बेकिस्तान हैं।

सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

PIB, (17 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यबल की रिपोर्ट को मंजूरी दी है।
- गृह मंत्रालय ने कार्यबल का गठन इसलिए किया था, ताकि सीमा प्रबंधन के सुधार में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए क्षेत्रों की निशानदेही की जा सके।
- कार्यबल का नेतृत्व संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंधन) ने किया और उसके सदस्यों में सीमा प्रहरी बलों, अंतरिक्ष विभाग तथा सीमा प्रबंधन प्रभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
- गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बलों, इसरो, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय और रक्षा मंत्रालय सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।



अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु निम्न क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है:

- द्वीप विकास
- सीमा सुरक्षा
- संचार और नौवहन
- जीआईएस और संचालन आयोजना प्रणाली
- सीमा संरचना विकास

मुख्य बिंदु

- परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसे पांच वर्षों

में पूरा किया जाएगा। इसके साथ नजदीकी सहयोग किया जाएगा।

- सीमा प्रहरी बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। लघु कालीन आवश्यकताओं के तहत सीमा प्रहरी बलों के लिए हाई रिजॉल्यूशन इमेजरी और संचार के लिए बैंडविथ का प्रबंध किया जाएगा।



Ministry of Home Affairs Government of India

- मध्यम अवधि की आवश्यकता के मद्देनजर इसरो एक उपग्रह लांच कर रहा है, जिसका इस्तेमाल केवल गृह मंत्रालय करेगा।
- दीर्घकालीन अवधि के तहत गृह मंत्रालय नेटवर्क अवसंरचना विकसित करेगा ताकि अन्य एजेंसियां उपग्रह संसाधनों को साझा कर सकें।
- दूरदराज के इलाकों में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उपग्रह संचार की सुविधा दी जाएगी।
- इस परियोजना से द्विपीय एवं सीमा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और सीमा एवं द्विपीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास में मद्दद मिलेगी।
- इसरो गृह मंत्रालय के लिए एक विशिष्ट उपग्रह प्रक्षेपित करेगा ताकि उसे अन्य देशों से लगी अपनी सीमाओं को और मजबूत बनाने में मद्दद मिल सके।

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

PIB, (19 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
संबंधित मंत्री – राज्यवर्धन सिंह राठौर

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय सिनेमा के एक सदी से अधिक पुराने इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय (National Museum of Indian Cinema-NMIC) का निर्माण किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस संग्रहालय का निर्माण 140.61 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
- यह संग्रहालय श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में संग्रहालय सलाहकार

समिति (Museum Advisory Committee) के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है तथा प्रसून जोशी की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस संग्रहालय को उन्नत बनाने में सहयोग किया है।

- यह संग्रहालय दो इमारतों- 'नवीन संग्रहालय भवन' (New Museum Building) और 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महल 'गुलशन महल' (Gulshan Mahal) में स्थित है। ये दोनों इमारतें मुंबई में फिल्म प्रभाग (Films Division) परिसर में हैं।



नवीन संग्रहालय भवन में चार प्रदर्शनी हॉल मौजूद हैं-

- **गांधी और सिनेमा:** यहाँ महात्मा गांधी के जीवन पर बनी फिल्में मौजूद हैं। इसके साथ सिनेमा पर उनके जीवन के गहरे प्रभाव को भी दिखाया गया है।
- **बाल फिल्म स्टूडियो:** यहाँ आण्टुकों, विशेष रूप से बच्चों को फिल्म निर्माण के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला को जानने का मौका मिलेगा।
- **प्रौद्योगिकी, रचनात्मकता और भारतीय सिनेमा:** यहाँ भारतीय फिल्मकारों द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की जानकारी मिलेगी। रजत पटल पर फिल्मकारों के सिनेमाई प्रभाव को भी पेश किया गया है।
- **भारतीय सिनेमा:** यहाँ देशभर की सिनेमा संस्कृति को दर्शाया गया है।

गुलशन महल

- गुलशन महल को मूल रूप से गुलशन आबाद (समृद्धि का बगीचा) के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 1800 शताब्दी के मध्य में किया गया था। इस पर 'खोजा मुस्लिम समुदाय' के एक गुजराती व्यापारी 'पीरभॉय खलकदिना' का स्वामित्व था।
- गुलशन महल ASI ग्रेड- II धरोहर संरचना है। NMIC परियोजना के हिस्से के रूप में इसकी मरम्मत की गई है।
- यहाँ पर भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष से अधिक समय की यात्रा दर्शाई गई है।

इसे 9 वर्गों में विभाजित किया गया है-

- सिनेमा की उत्पत्ति
- भारत में सिनेमा का आगमन
- भारतीय मूक फिल्म



- ध्वनि की शुरूआत
- स्टूडियो युग
- द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव
- रचनात्मक जीवंतता
- नई विचारधारा और उससे आगे/न्यू वेव एंड बियॉन्ड
- क्षेत्रीय सिनेमा

प्रवासी भारतीय दिवस

PIB, (21 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – विदेश मंत्रालय
संबंधित मंत्री – सुषमा स्वराज

संदर्भ

- हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां संस्करण 21 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुआ।
- प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bhartiya Divas, 2019) के लिए इस बार वाराणसी में बेहद खास आयोजन किया गया।

15th

**प्रवासी भारतीय दिवस
PRAVASI BHARATIYA DIVAS**



2019

- प्रवासी भारतीय दिवस समारोह वाराणसी में 21 से 23 जनवरी तक चला।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2019 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश), में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- पहली बार वाराणसी में 21 से 23 जनवरी, 2019 तक तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

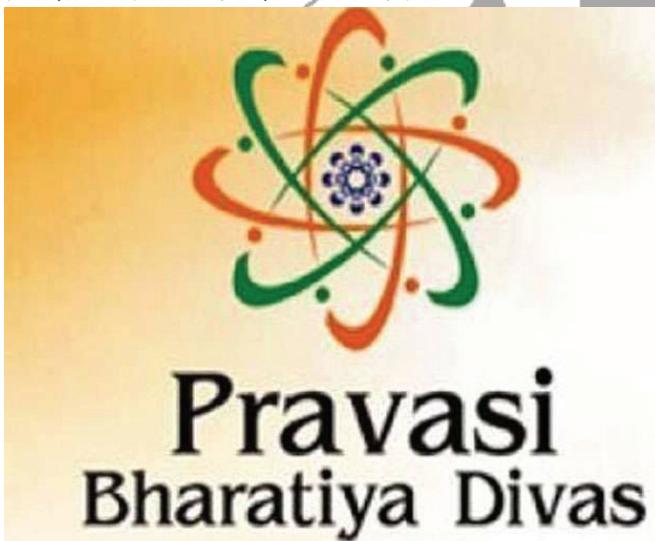
मुख्य अतिथि

- मौरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 15वें संस्करण के मुख्य अतिथि रहे।
- नॉर्वे के सांसद हिमांशु गुलाठी विशिष्ट अतिथि और न्यूजीलैण्ड के सांसद कंवलजीत सिंह बक्शी सम्मानित अतिथि रहे।

उद्देश्य और विषय

- प्रवासी भारतीय दिवस का मकसद भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाने से है।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का विषय है- नये भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका।

प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करना



- इस सम्मेलन में विदेश में रह रहे उन भारतीयों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित किया हो।
- देश का नाम रौशन करने वाले ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के हाथों प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा जाता है।
- इसके अलावा इस सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों से जुड़े मामलों और समस्याओं पर भी विचार किया जाता है।
- यह प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां आयोजन है, इससे पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी को या उसके आस-पास होता आया था।
- सम्मेलन के बाद प्रतिभागियों ने 24 जनवरी को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज की यात्रा की।



क्या है प्रवासी भारतीय दिवस?

- प्रवासी दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 से हुई थी।
- इस मौके पर हर साल भारत सरकार अमूमन तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करती है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया था।
- पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में हुआ था।
- प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये थे।
- यह आयोजन विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय को सरकार के साथ काम करने और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का मंच उपलब्ध कराता है।
- सम्मेलन के दौरान भारत और विदेश दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चुने गये भारतीय प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किये जाते हैं।

विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट्स में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय बंदरगाह

PIB, (22 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – पोत परिवहन मंत्रालय

संबंधित मंत्री – श्री नितिन गडकरी

संदर्भ

- हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट्स में शुमार हो गया है।





PIB PICTURE



- लॉयड्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जेएनपीटी ने अपने पिछले स्थान से पांच स्थान ऊपर आकर सूची में 28वां स्थान प्राप्त किया है।
- यह बंदरगाह की व्यापक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जेएनपीटी द्वारा किये जा रहे प्रयासों और कार्यान्वित किये जा रहे कार्यनीतिक कदमों का प्रमाण है।

मुख्य बिंदु

- जेएनपीटी ने अपने नियात-आयात साझेदारों के लिए खेप की बेहतर निगरानी और व्यापार प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अपनी ऐप सेवा भी शुरू की है।
- इस ऐप की बदौलत व्यापारी अपनी खेप तथा बंदरगाह के यातायात और मौसम संबंधी अपडेट के बारे में सभी प्रकार की उपयुक्त जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
- यह ऐप नियमित अंतराल पर उपयुक्त जानकारी को अद्यतन करता रहेगा, ताकि व्यापारी नवीनतम जानकारी से लैस रहें।
- यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध होगा। इस ऐप को जेएनपीटी के अध्यक्ष हितधारकों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय पंचाट

PIB, (23 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – वित्त मंत्रालय
संबंधित मंत्री – अरुण जेटली

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय पंचाट (Goods and Services Tax Appellate Tribunal – GSTAT) के लिए एक राष्ट्रीय बैंच की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

- यह बैंच नई दिल्ली में होगी।
- इसमें एक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) होंगे।
- यह बैंच GST कानूनों से सम्बंधित द्वितीय अपील का मंच होगी।
- केंद्र और राज्यों के बीच GST से सम्बन्धित विवाद के निपटारे के लिए यह बैंच सर्वोपरि मंच होगी।
- अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील में दिए गये आदेशों के विरुद्ध इस बैंच के समक्ष अपील की जा सकेगी।

संशोधन का वैधानिक आधार

- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (CGST act) में यह प्रावधान है कि GST से सम्बन्धित विवादों की अपील सुनने के लिए और उनकी समीक्षा करने के लिए एक तन्त्र होगा।

- इस प्रकार के तंत्र की स्थापना का अधिकार अधिनियम में केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार परिषद् की अनुशंसा पर अधिसूचना निकालकर एक अपीलीय पंचाट (Appellate Authority or the Revisional Authority) का गठन करेगी।
- केंद्र सरकार को प्रदत्त इसी अधिकार के तहत प्रस्तावित संशोधन तैयार किये गये हैं और उन पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ली गई है।



महत्व

- GST अपीलीय पंचाट पूरे भारतवर्ष के लिए एक सर्वोपरि मंच है जहाँ अपीलों की अंतिम सुनवाई होगी।
- इस प्रकार GST के अन्दर उठने वाले विवादों के निपटारे में तथा GST के कार्यान्वयन में समरूपता आएगी।

‘सी विजिल’ तटीय रक्षा अभ्यास

PIB, (23 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – रक्षा मंत्रालय
संबंधित मंत्री – निर्मला सीतारामण

संदर्भ

- हाल ही में देश में सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निकटवर्ती सम्बन्ध से भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित प्रथम तटीय रक्षा युद्धाभ्यास ‘सी विजिल’ 23 जनवरी, 2019 को समाप्त हो गया।
- हालिया समय में देश द्वारा देखा गया अब तक का अपने प्रकार का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था एवं इसमें 100 से अधिक पोत, बायुयान एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित गश्ती नावों ने भागीदारी की।

मुख्य बिंदु

- भारतीय नौसेना ने 22 जनवरी, 2019 को सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास आरम्भ किया। यह युद्धाभ्यास “26/11” हमले के दस साल पूरे होने पर किया गया था।



- इस अभ्यास कोडनेम 'सी विजिल 2019' दिया गया।
- यह युद्धाभ्यास दो दिवसीय है।
- इस युद्धाभ्यास में मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले समुद्राय ने भी भाग लिया है।
- अभ्यास में रक्षा मंत्रालय के अलावा, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, मत्स्य पालन, कस्टम के अलावा राज्य सरकारें भी शामिल हुई।



- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य इस बात की जाँच करना है कि 26/11 के बाद तटों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम आखिर कितने कारगर साबित हुए हैं।
- सी विजिल के साथ ऑपरेशनल, टेक्निकल और प्रशासनिक ऑडिट भी किया जाएगा, जो हमारी ताकत और कमज़ोरी के बारे में सही जानकारी देगा।

भारत-अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (आईएएफटीएक्स) - 2019

PIB, (23 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – रक्षा मंत्रालय
संबंधित मंत्री – निर्मला सीमारमण

संदर्भ

- हाल ही में भारत-अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (आईएएफटीएक्स)-2019 की तैयारियों से संबंधित कार्यरूप को अंतिम रूप देने के लिए 23-24 जनवरी, 2019 को पुणे में एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
- इस सम्मेलन में मिस्र, घाना, नाइजीरिया, सेनेगल, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, युगांडा, नाइजर और जाम्बिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मुख्य बिंदु

- भारत-अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (आईएएफटीएक्स), 2019 18 से 27 मार्च, 2019 तक पुणे के औंध मिलिट्री स्टेशन और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में होगा।
- यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और एक दर्जन से अधिक अफ्रीकी देशों के साथ किया जा रहा है।



Ministry of Defence Government of India

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों को बढ़ाने और संयुक्त शांति अभियानों को गति देना है।
- इस अभ्यास से संबंधित प्रारंभिक योजना दिसंबर, 2018 में आयोजित सम्मेलन में ही तैयार कर ली गयी थी।
- आईएएफटीएक्स-2019 अफ्रीकी महाद्वीप के सदस्य राष्ट्रों के साथ बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संबंधों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- इससे इन देशों के साथ पहले से ही मजबूत रणनीतिक सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।

आईएएफटीएक्स कोहासा

PIB, (24 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – रक्षा मंत्रालय
संबंधित मंत्री – निर्मला सीमारमण

संदर्भ

- हाल ही में एडमिरल सुनील लांबा पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, चैयरमैन सीओएससी और नौसेना प्रमुख ने 24 जनवरी, 2019 को अंडमान-निकोबार स्थित नौसेना वायु स्टेशन आईएएफटीएक्स शिखपुर की आईएएफटीएक्स कोहासा के रूप में शुरूआत की।
- आईएएफटीएक्स कोहासा को यह नाम व्हाइट बैलिड सी ईंगल के नाम पर दिया गया है जो अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का स्थानीय बड़ा शिकारी पक्षी है।



- इस भव्य समारोह में वाइस एडमिरल विमल वर्मा, एवीएसएम, एडीसी कमांडर-इन-चीफ, अंडमान-निकोबार कमान सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- समारोह कार्यक्रम में औपचारिक गॉर्ड प्रस्तुति कमीशनिंग छोटी पताका फहराना और कमांडिंग अधिकारी, कमांडर कुलदीप त्रिपाठी द्वारा जहाज का बारंप पढ़ना शामिल थे।

नौसेना वायु स्टेशन - आईएनएस कोहासा

- नौसेना वायु स्टेशन शिबपुर को उत्तरी अंडमान में निगरानी बढ़ाने के लिए एक फारवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस (एफओएबी) के रूप में वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। अब इसे आईएनएस कोहासा के रूप में शुरू किया गया है।
- कोको आइलैंड (म्यांमार) के नजदीक स्थित होने और भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन ईंजेड के व्यापक विस्तार के कारण यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिसंपत्ति बन जाता है।
- एयरफील्ड भारतीय वायु सेना और तटरक्षक विमानों के लिए विलग परिचालन उपलब्ध कराता है।
- यह वायु स्टेशन शॉर्ट रेंज मेरीटाइम टोही (एसआरएमआर) वायुयान और हैलीकॉप्टर संचालित करता है।



- यह वायुयान स्टेशन दायित्व के एनसी क्षेत्र में ईंजेड निगरानी एन्टी पोचिंग मिशन खोज और बचाव (एसएआर) और मानवीय सहायता आपदा राहत एचएडीआर मिशन संचालित करता है।
- मलेशियाई एयरलाइन फ्लाइट 370 के खोज परिचालनों के दौरान नौसेना और तटरक्षक के डार्नियर डीओ 228 इसी बेस से परिचालित हुए थे।
- नीति आयोग ने एनएस कोहासा की समावेशी द्वीप विकास के एक हिस्से के रूप में एक 'अलीं बर्ड' के रूप में पहचान की थी।
- इस दिशा में एनएस कोहासा नामिक उड़ान परिचालन में सहायता प्रदान करने के लिए यह सभी तरह से तैयार है।
- इसका रन-वे बढ़ाकर दस हजार फुट करने की भी योजना है ताकि निकट भविष्य में यह बड़ी बॉडी के वायुयानों का परिचालन भी कर सके।

कलामसैट और माइक्रोसैट आर

PIB, (25 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – अंतरिक्ष विभाग

संबंधित मंत्री – ए.एस. किरण कुमार

संदर्भ

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 24 जनवरी, 2019 को विश्व के सबसे छोटे सैटेलाइट 'कलामसैट' को लॉन्च किया।
- पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-44 के द्वारा कलामसैट और माइक्रो सैट-आर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश ध्वन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया।
- कलामसैट की खासियत यह है कि इसे छात्रों ने विकसित किया है। इसके अलावा, माइक्रोसैट-आर की खासियत है कि यह अन्तरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है।
- इसरो की ओर से जारी मिशन की जानकारी के अनुसार, श्रीहरिकोटा के सतीश ध्वन स्पेस सेंटर से PSLV C-44 के लॉन्चिंग सुचारू रूप से आरंभ की गई। यह इसरो के पीएसएलवी व्हीकल की 46वीं उड़ान है।



कलामसैट की विशेषताएं

- कलामसैट दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट है। कलामसैट सैटेलाइट को भारतीय छात्रों के एक समूह ने तैयार किया है।
- इसका नामकरण देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है।
- यह नौसैटेलाइट 10 सीएम क्यूब के साथ 1.2 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट है।
- इसको बनाने में कुल 12 लाख रुपए का खर्च आया है।
- इस सैटेलाइट को हाई स्कूल के छात्रों ने तैयार किया है। इस टीम को रिफत शरूक लीड कर रहे थे। शरूक की उम्र 18 साल है और वे तमिलनाडु के पालापत्ती के रहने वाले हैं।
- यह दुनिया का सबसे हल्का और पहला 3डी प्रिंटेंड सैटेलाइट है।
- छात्रों द्वारा तैयार किए गए पे-लोड को पीएस-4 में फिट करके अंतरिक्ष भेज दिया गया।

- कलामसैट इतना छोटा है कि इसे 'फेन्टो' की श्रेणी में रखा गया है। पीएस-4 लॉन्चिंग पैड का वह हिस्सा है जिसमें चौथे चरण का प्यूल भरा जाता है।



पीएसएलवी-सी44 मिशन

- पीएसएलवी-सी44 ने उड़ान भरने के लगभग 14 मिनट बाद इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट आर को 277 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग कर दिया।
- अलग होने के बाद इसने लगभग 103वें मिनट में 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर काम करना शुरू कर दिया।
- कलामसैट सैटेलाइट रॉकेट के चौथे चरण को कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेगा।
- रॉकेट ने अपने चौथे चरण में कलामसैट को अत्यधिक ऊंचाई वाली कक्ष में स्थापित कर दिया, जहां से वह परीक्षण कार्यों को अंजाम दे रहा है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

PIB, (25 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – निर्वाचन आयोग
संबंधित मंत्री – ओम प्रकाश रावत

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आठवां मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2019 को देश भर में मनाया गया।



- इस महत्वपूर्ण दिवस का आयोजन सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है और साथ ही यह भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है।
- भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इस दिन को देश के लोकतंत्र का त्योहार भी कह सकते हैं। इस दिन वोट देने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जश्न का दिन होता है।

- यह दिवस मतदाताओं में मतदान प्रक्रिया में कारगर भागीदारी के बारे में जानकारी फैलाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

उद्देश्य और विषय

- इस दिवस का उद्देश्य देश में मतदाताओं की संख्या बढ़ाना, विशेषकर नए मतदाताओं को इससे जोड़ना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश के वोटरों को उनके अधिकारों और लोकतंत्र के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाना है।
- इस साल ये नौवां मतदाता दिवस है। इस बार की थीम – 'कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए (No Voter to be Left Behind)' रखी गई।



9वां मतदाता दिवस

- इस बार चुनाव आयोग ने 9वें मतदाता दिवस पर देश भर में छह लाख से ज्यादा जगहों पर और 10 लाख के आसपास पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता दिवस मनाया गया।
- इन कार्यक्रमों में नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया और उनको मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए आवेदन दिए गये।

भारत निर्वाचन आयोग की शुरुआत

- भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था।
- भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही वर्ष 2011 से 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी।

भारतीय चुनाव आयोग

- भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधिक संस्थानों में जन प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था।
- आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
- संसद के दोनों सदनों-लोकसभा और राज्य सभा के लिए चुनाव बेरोक-टोक और निष्पक्ष हों, इसके लिए एक स्वतंत्र चुनाव (निर्वाचन) आयोग बनाया गया है।

सौर ऊर्जा और जल उपचार प्रौद्योगिकी मिशन केन्द्र

PIB, (25 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संबंधित मंत्री – हर्षवर्धन

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने चेन्नई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम) में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा स्थापित तीन प्रमुख केंद्रों का शुभारंभ किया।

सौर ऊर्जा केंद्र

- इन तीनों में पहले डीएसटी- आईआईटीएम सोलर एनर्जी हारनेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है।
- इस केंद्र में सिलिकॉन सोलर सेल जैसी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
- सिलिकॉन सोलर सेल उच्च दक्षता से युक्त हैं और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं।
- इस केंद्र में नियुक्त अनुसंधानकर्ताओं के नेटवर्क में आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, अन्ना विश्वविद्यालय, आईसीटी मुंबई, बीएचईएल और केजीडीएस के वैज्ञानिक शामिल हैं।

- यह बहुविध संस्थागत वर्चुअल केंद्र, अपशिष्ट जल उपचार, पुनःउपयोग, तूफान जल प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण स्थापित करेगा।



सोलर थर्मल केंद्र

- तीसरा केंद्र 'द टेस्ट बेड ऑन सोलर थर्मल डिसेलिनेशन सोल्यूशन्स' होगा।
- इसे तमில்நாடு में रामनाथपुरम जिले के नारिपयूर में एक समाधान प्रदाता के रूप में आईआईटी मद्रास और इम्पीरियल केजीडीएस द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य बंगल की खाड़ी के तट पर स्थित शुष्क तटीय गांव में मौजूद जल चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी समाधान उपलब्ध कराना है।
- इसके विकास से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए तटीय क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकीय जल समाधान उपलब्ध होंगे।

एलीफेंटा गुफाओं में 'आर्टिजन स्पीक'

PIB, (26 Jan.)

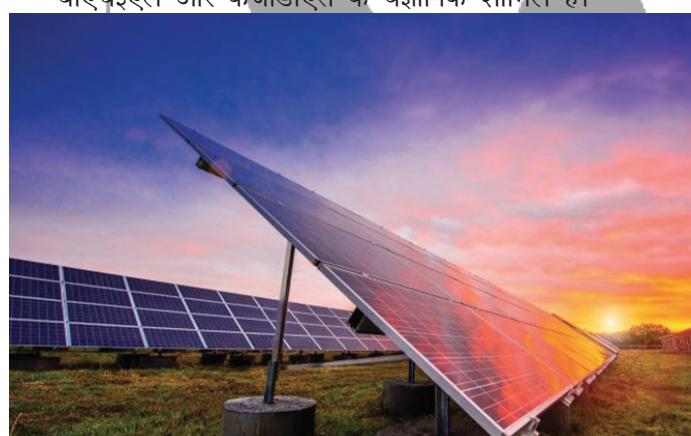
संबंधित मंत्रालय – वस्त्र मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी

संदर्भ

- हाल ही में भारत के हस्तकरघा और वस्त्र क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक अनूठे कार्यक्रम 'आर्टिजन स्पीक' का आयोजन किया गया है जहाँ भारत के समृद्ध हस्तकरघा और वस्त्र परंपरा को प्रदर्शित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम का आयोजन 28 जनवरी, 2019 को मुंबई के निकट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एलीफेंटा गुफा में किया गया।
- यह ऐतिहासिक अवसर भारतीय हस्तकरघा के विकास की दिशा में निजी क्षेत्र द्वारा की जा रही बड़ी प्रतिबद्धताओं की एक नई शुरुआत का भी साक्षी बनेगा।



जल उपचार केंद्र

- दूसरा केंद्र डीएसटी-आईआईटीएम वॉटर-आईसी पॉर एसयूटीआरएएम ऑफ ईजी वॉटर (निपुण, सस्ते और समाधानों के लिए सतत उपचार, पुनः उपयोग और प्रबंधन के लिए डीएसटी-आईआईटीएम वॉटर इनोवेशन सेंटर) है।
- इसे अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल उपचार, सेंसर विकास, तूफान के जल के प्रबंधन, वितरण और एकत्रीकरण प्रणालियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समावेशी अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

- सरकार एवं अग्रणी रिटेलर तथा टेक्सटाइल ब्रांडों के बीच सहयोग समझौतों से हस्तकरघा संवर्द्धन को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके फलस्वरूप बुनकरों को बेहतर मूल्य भी प्राप्त होगा तथा उनकी बाजार समझ में भी सुधार आएगा।
- इस कार्यक्रम में अग्रणी डिजाइनरों की प्रतिभागिता के साथ एक मोहक सांस्कृतिक शो के जरिए भारतीय वस्त्रों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया गया।
- कारीगरों के साथ स्थापित एवं उभरते डिजाइनरों की प्रस्तुति भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जीआई (भौगोलिक संकेतक) पर आधारित थी।



उद्देश्य

- बड़े ब्रांडों एवं हैंडलूम क्लस्टरों के बीच कार्यनीतिक साझेदारी का उद्देश्य एक तरफ प्रमुख कंपनियों और हस्तकरघा बुनकरों के बीच दीर्घकालिक बाजार संपर्क की स्थापना करना है तथा दूसरी तरफ यह क्षेत्र का स्थाई विकास भी सुनिश्चित करेगा, जिससे बुनकरों के लिए आय के टिकाऊ और बड़े अवसर प्राप्त होंगे।
- यह जीआई वस्त्रों की क्षमता को प्रदर्शित करेगा, जिससे कि ऐसे उत्पादों का निर्माण किया जा सके एवं उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।
- साथ ही, यह जमीनी स्तर के हितधारकों की आपूर्ति शृंखला क्षमता और कौशलों का भी सुदृढ़ बनाएगा।

मोबाइल ऐप 'आरडीपी इंडिया- 2019'

PIB, (27 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – रक्षा मंत्रालय
संबंधित मंत्री – निर्मला सीमरण

संदर्भ

- हाल ही में सरकार के 'डिजिटल इंडिया' अभियान के अनुपालन में रक्षा मंत्रालय ने एक नई पहल की शुरुआत की।
- इसके तहत गणतंत्र दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप 'आरडीपी इंडिया 2019' को जारी किया।
- इसका उद्देश्य गणतंत्र दिवस समारोह की रूपरेखा को राजपथ

पर मौजूद दर्शकों के अलावा दुनिया भर के आम लोगों को उपलब्ध कराना था।



मुख्य बिंदु

- इस ऐप में नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड की सूचना मौजूद है, जिसमें परेड के क्रम, विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत ज्ञाकियों का विवरण, बच्चों के सांस्कृतिक प्रदर्शनों, फ्लाई-पास्ट तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 के विजेताओं के नामों की जानकारी दी गई है।
- परेड में उपस्थित सभी दर्शकों के लिए यह ऐप बहुत सूचनात्मक रहा और इसकी हर तरफ प्रशंसा की गई। इस ऐप में परेड की लाइव-स्ट्रीमिंग का भी प्रावधान था।
- ज्ञाकियों में प्रस्तुत विषय और विचारों को जानने की इच्छा रखने वाले लोगों तथा जो लोग किसी कारणवश राजपथ या टीवी पर परेड नहीं देख सके, वे लोग ऐप को डाउनलोड करके यह परेड अब भी देख सकते हैं और आयोजन के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

बाघ संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन

PIB, (28 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संबंधित मंत्री – डॉ. हर्षवर्धन

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा 28 जनवरी, 2019 को बाघ संरक्षण पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन की रेंज में तीसरा सम्मेलन है। यह वर्ष 2012 के बाद भारत में आयोजित होने वाला दूसरा समीक्षा सम्मेलन है।
- सम्मेलन में बाघ रेंज के 13 देशों द्वारा वैश्विक बाघ पुनःप्राप्ति

कार्यक्रम (जीटीआरपी) की स्थिति और वन्य जीव तस्करी से निपटने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।



सुरक्षा ऑडिट पूरा

- देश के 50 में से 25 बाघ अभ्यारण्यों का सुरक्षा ऑडिट पूरा हो चुका है और सरकार का कहना है कि वह बांधों के संरक्षण में हर प्रकार की मदद देने के लिए तैयार है।

बांधों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प

- बाघ रेंज के देशों ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में घोषणा के दौरान वर्ष 2022 तक अपनी-अपनी रेंज में बांधों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प व्यक्त किया था।
- सेंट पीटर्सबर्ग चर्चा के समय भारत में 1411 बाघ होने का अनुमान था जो कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान वर्ष 2014 के तीसरे चक्र के बाद दोगुना होकर 2226 हो गया है।
- ऐसा महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचकांकों (केपीआई) के अनुरूप काम करने से हुआ। इन सूचकांकों में बाघ के रिहायशी क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाना और जुर्मानों में वृद्धि करना है। अभी अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 का चौथा चक्र जारी है।



दूसरा समीक्षा सम्मेलन

- भारत में वर्ष 2012 के बाद होने वाला यह दूसरा समीक्षा सम्मेलन है।

- तीसरे समीक्षा सम्मेलन में बाघ रेंज के 13 देशों द्वारा वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम (जीटीआरपी) की स्थिति और वन्य जीव तस्करी से निपटने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बाघ रेंज के देशों विशेषकर भारत के श्रेष्ठ व्यवहारों को प्रदर्शित किया जाएगा।

पड़ोसी बाघ रेंज देश

- इस समीक्षा सम्मेलन से अलग भारत ने पड़ोसी बाघ रेंज देशों - बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल के साथ उपमहाद्वीप स्तर के बाघ अनुमान रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है।

नमक सत्याग्रह स्मारक

PIB, (30 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में महात्मा गाँधी की 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुजरात के नवसारी जिले के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का लोकार्पण किया गया।
- इस स्मारक में महात्मा गाँधी के आदर्श, यथा - स्वदेशी आग्रह, स्वच्छता आग्रह और सत्याग्रह का वर्णन एवं चित्रण हुआ है।

महत्व

- इस स्मारक का उद्देश्य राष्ट्र के लोगों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किये गये बलिदानों का स्मरण दिलाना था।
- साथ ही यह गाँधीजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले सत्याग्रहियों के प्रति श्रद्धांजलि भी है। यह स्मारक पर्यटकों को आकर्षित करेगा।



नमक सत्याग्रह के बारे में?

- 12 मार्च, 1930 को महात्मा गाँधी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक नमक यात्रा आरम्भ की थी।
- यात्रा के अंत में वे दांडी नामक तटीय गाँव में पहुँचे थे और वहाँ ब्रिटिशों द्वारा नमक पर लगाये गये अत्यंत बढ़े हुए कर का विरोध किया था।
- यह नमक यात्रा 12 मार्च, 1930 से लेकर 6 अप्रैल, 1930 तक चली थी।

- 24 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा हिंसारहित रही और इसका यह ऐतिहासिक महत्व है कि इसके उपरान्त देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात हो गया।
- दांडी के समुद्र तट पर पहुँच कर महात्मा गाँधी ने अवैध रूप से नमक बनाकर कानून अवहेलना की थी।
- इनके देखा-देखी पूरे भारत में लाखों लोगों ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन किया जिसमें नमक बनाकर अथवा अवैध नमक खरीद कर नमक कानूनों को तोड़ा गया।



ऐतिहासिक भूमिका

- उस समय ब्रिटिशों ने भारतीयों को नमक बनाने और बेचने से मना कर दिया था। साथ ही भारतीयों को नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ को ब्रिटिशों से खरीदने के लिए विवश कर दिया था।
- इस प्रकार जहाँ ब्रिटिशों को नमक बनाने और बेचने का एकाधिकार प्राप्त हो गया था, वहीं वे भारी नमक कर भी लगा रहे थे।
- नमक यात्रा ब्रिटिशों के इस अत्याचार के विरुद्ध एक जन-आन्दोलन में बदल गया।

सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना

PIB, (30 Jan.)

संबंधित मंत्रालय – पर्यटन मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री के.जे. अल्फोंस

संदर्भ

- हाल ही में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री के.जे. अल्फोंस ने सिक्किम में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया।
- इस परियोजना को मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत लागू किया गया है।
- केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना को 98.05 करोड़ रुपये की लागत से जून, 2015 में मंजूरी दी थी। इस योजना के अंतर्गत सिक्किम में यह पहली परियोजना है।
- इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने पर्यटन बुनियादी ढांचा सुविधाएं

जैसे पर्यटन सूचना केन्द्र, ध्यान केन्द्र, ऑर्गेनिक इको पर्यटन केन्द्र, लॉग हट, जिप लाइन, फूलों के लिए प्रदर्शनी केन्द्र, उद्यान पथ, स्मारिका दुकानें, कैफेटेरिया, बारिश से बचने की जगह, सड़क के किनारे सुविधाएं, अंतिम मील तक संपर्क पार्किंग, सार्वजनिक शैचालय आदि विकसित किए जाएंगे।



Ministry of Tourism Government of India

स्वदेश दर्शन योजना

- स्वदेश दर्शन योजना का 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में विषय आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य के साथ शुभारम्भ किया गया।
- स्वदेश दर्शन योजना को एक समन्वित तरीके से उच्च पर्यटन मूल्य, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता के सिद्धांतों पर विकसित किया जाएगा।
- योजना सभी हितधारकों की चिंताओं, पर्यटन के अनुभव को समृद्ध और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है।
- योजना के तहत 13 विषयगत सर्किट की विकास हेतु पहचान की गई है, जो निम्न हैं: पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेर्जट सर्किट, आदिवासी सर्किट, पारिस्थितिकी सर्किट, बन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट और विरासत सर्किट।



पर्यटन मंत्रालय
की मुख्य उपलब्धियां

योजना की विशेषताएं

- योजना के हिस्से के तौर पर देश भर में संरचनात्मक विकास के लिए विषय आधारित पर्यटन सर्किटों की पहचान की जाएगी।
- विषय आधारित पर्यटन सर्किट (टीबीटीसी) को धर्म, संस्कृति, जातीयता, स्थान आदि जैसे विशेष विषयों पर बने पर्यटन सर्किट के तौर पर परिभाषित किया जाता है।
- टीबीटीसी एक राज्य में भी हो सकता है या यह एक ऐसा क्षेत्रीय सर्किट हो सकता है जिसमें एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हों।



PIB PICTURE



संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहमति पत्र हस्ताक्षर को मंजूरी दी?
- खान, परीक्षण और अनुसंधान केंद्र में सुरक्षा से
 - पर्यटन क्षेत्र में
 - अंतरिक्ष क्षेत्र में
 - समुद्र विज्ञान एवं संचार
2. 'भारतीय निर्यात-आयात बैंक' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- यह बैंक भारत के लिए प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी है।
 - इसका पुनर्पूजीकरण किया जाएगा, जिसका बॉण्ड सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को जारी किए जाएंगे।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2
3. हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए प्रथम राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता प्रारंभ की गयी?
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय
 - खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय
 - जनजातीय कार्य मंत्रालय
 - रेल मंत्रालय
4. 'मतदाता जागरूकता मंच' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनवरी, 2019 में गुजरात से इसकी शुरूआत की गयी।
 - इस मंच को निर्वाचन आयोग के निर्वाचक साक्षरता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया।
 - इसकी पहल पिछले वर्ष 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर की गयी।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
- 1 और 2
 - 2 और 3
 - 1 और 3
 - 1, 2 और 3
5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- हाल ही में 9वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया।
 - 9वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन की थीम 'शेपिंग ऑफ ए न्यू इंडिया' थी।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
- 1 और 2
 - 2 और 3
 - 1 और 3
 - 1, 2 और 3
6. सीमा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग हेतु निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को चिह्नित किया गया?
- द्वीपीय विकास
 - सीमा सुरक्षा
 - संचार और नौवहन
 - जीआईएस और संचालन आयोजना प्रणाली
 - सीमा संरचना विकास
- कूट:
- 1, 2, 3 और 5
 - 2, 3, 4 और 5
 - 1, 3, 4 और 5
 - उपर्युक्त सभी
7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- हाल ही में मुम्बई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किया गया है।
 - भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय, नवीन संग्रहालय भवन और गुलशन महल में स्थित है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1, न ही 2
8. '2019 में प्रवासी भारतीय दिवस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- इसके 15वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया।
 - इसके मुख्य अतिथि मौरीश संप्रदाय के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ थे।
 - इस सम्प्रलङ्घन की थीम- 'नये भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका' थी।
- उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
- 1 और 2
 - 2 और 3
 - 1 और 3
 - 1, 2 और 3
9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- हाल ही में लॉयड्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट्स की सूची में 28वां स्थान प्राप्त हुआ है।
 - यह विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर में सूचीबद्ध होने वाला द्वितीय कंटेनर पोर्ट्स है।



PIB PICTURE



ANSWER KEY

01-15 जनवरी को दिए गए संभावित प्रश्न (प्रीलिम्स का उत्तर)...